Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

बेरोजगारीः पृष्ठभूमि एवं कारण

डॉ0 अवधेश कुमार दूबे
असि0 प्रोफेसर
कमला नेहरू विधि संस्थान, सुलतानपुर

डॉ0 शिव प्रताप शुक्ला
असि0 प्रोफेसर

शोध पत्र

बेरोजगारी वर्तमान आर्थिक सन्दर्भों में एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। समस्या के कारण विश्व के लगभग सभी विकासशील देशों में जटिल आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गये हैं। अधिकांश अल्प विकसित देश आज बेरोजगारी और अर्द्ध–बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बुनियादी तौर पर पहचाने जाते हैं। अल्प विकसित देशों के बेरोजगारी की समस्या विकसित देशों की आर्थिक समस्याओं से मौलिक रूप से भिन्न है। विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या मात्र एक सामाजिक समस्या है, आर्थिक अभिशाप नहीं, इसलिए विकसित तथा विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्याओं में मौलिक व संरचनात्मक अन्तर विद्यमान हैं। विकासशील देशों में जो विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी दिखायी पड़ती है, वह मुख्यतः पूँजी निर्माण की कमी से उत्पन्न होती है, जब कि विकसित देशों में बेरोजगारी अधिकांशतः सम्पूर्ण–माँग में अभाव के कारण पैदा होती है, जो चक्रीय प्रकृति की होती है। विकासशील और विकसित देशों में बेरोजगारी सदैव अर्थशास्त्रियों और प्रशासकों के लिए चुनौती भरी और हताश करने वाली समस्या रही है। बेरोजगारी की समस्या और उसकी व्यापकता मूलतः अर्थव्यवस्था की पूँजीवादी व्यवस्था से सम्बद्ध है।

विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या ऐसे अनेक आयामों से युक्त है, जो विकसित देशों में बेरोजगारी के विश्लेषण करने के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। बेरोजगारी से सदैव आर्थिक और सामाजिक स्तर पर दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह केवल सामाजिक समस्या नहीं हैं, बल्कि एक मानवीय समस्या भी है। आधुनिक आर्थिक उन्नति और नवीनीकरण की प्रवृत्ति के कारण पूँजी निर्माण विकासशील देशों की एक ऐसी आवश्यकता बन गयी है, जो अन्ततः मशीनीकरण की जरूरत को जन्म देती है। इससे इस तरह के आर्थिक असंतुलन पैदा हो गये हैं, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध एक ओर तो गरीबी से है, मगर दूसरी ओर बेरोजगारी

Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

और अर्द्धबेरोजगारी के उस स्तर से है जो बचत और निवेश के निम्नस्तरों से सम्बद्ध है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों विकासशील देशों में अब नयी ऊँचाईयाँ प्राप्त कर गये हैं। इसके आयाम भी नये हैं। यद्यपि विकासशील देशों में निवेश और उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है, लेकिन उत्पाद और प्रौद्यगिकी इतने पूँजी–परक हो गये हैं, कि रोजगार तदनुरूप अपेक्षितं स्तर तक नहीं बढ़ पाया है।

बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण और आकलन विकासशील देशों के सन्दर्भ में प्राथमिक विचारणीय बिन्दु बन चुका है। इसका महत्पूर्ण कारण यह कि प्रत्येक वर्ष जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है, जिनको रोजगार के उचित अवसर देने की आवश्यकता–पड़ती है। इन सन्दर्भों के अर्न्तगत भारत में भी बेरोजगारी अब एक जटिल समस्या बन चुकी है। आज उसका अनुमान लगाना तो आसान है, मगर इसे परिभाषित करना कठिन है। चूँकि बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी की स्थिति भारत में बहुत समय से चली आ रही है, अतः स्वतन्त्रता के बाद भी हमारे देश की सरकारों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन चुकी है। कुछ वर्ष–पूर्व ही इस समस्या ने अधिकांश अर्थशात्रियों का ध्यान आकर्षित कियाहै।बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में निदानात्मक उपायों के अर्न्तगत रोजगार परक उद्देश्यों को देश–में मुख्यतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद शामिल किया जाने लगा। बेरोजगारी सम्बन्धित मुद्दों के व्यापक अध्यंयन के उपेक्षा की इस समस्या का मुख्य कारण यह रहा है कि हमारा पूरा ध्यान केवल विकास पर था और यह माना जाता था कि इससे बेरोजगारी और अर्द्ध–बेरोजगारी की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। आज इस तथ्य को नश्चित तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि केवल आर्थिक–विकास, चाहे वह कितना तीव्र क्यों न हो, उससे बेरोजगारी की समस्या का समुचित समाधान नही हो सकता और सामाजिक समस्याएँ भी नहीं सुलझ सकती हैं। अतः वर्तमान आर्थिक परिवेश में सामाजिक–आर्थिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त. करने के लिए एक ठोंस तथा बहु–आयामी कार्यक्रम की आवश्यकता है, ताकि मानवीय संसाधन का बेहतर उपयोग सम्भव हो सके। बेरोजगारी की परिभाषा और उसकी अवधारणा के बारे में अलग–अलग मत प्रकट किये गये हैं। कुछ विचारक सोचते हैं कि बेरोजगारी का मूल अर्थ उन उपयुक्त व्यक्तियों को काम न मिलना है

Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

जो काम करने के इच्छुक हैं। उनके मतानुसार अपने आप काम से हट जाने को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। दूसरे वर्ग के विचारकों का मानना है कि जो भी व्यक्ति किसी काम से जुड़ा नहीं .है उसको बेरोजगार कहा जाता है। पहली तरह के विचार कों और दूसरी श्रेणी के विचारकों में बेरोजगारी की परिभाषा का अन्तर चाहे जो भी हो, परन्तु यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकार करने योग्य है कि–"बेरोजगारी एक आर्थिक बर्बादी है। समान्यतः रोजगार शब्द को जीविका के उस स्रोत से सम्बद्ध माना जाता है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब भी कोई व्यक्ति बिना काम कि ये अपनी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होता है, तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती और उस व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में नही रखा जा सकता। रोजगार शब्द सम्भवतः व्यक्तिगत स्तर से अधिक सम्बद्ध माना जाता है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मानवीय शक्ति के उपयोग की धारणा एक व्यापक अर्थ लिये हुए है, जिसका समृद्धि, सहभागिता और प्रगति के अर्थ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी न किसी उपाय से यदि आमदनी के अनेक साधन हैं तो स्वभावतः वह कभी रोजगार की तलाश नहीं करता और इस संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक– क्षमता (मानवीय क्षमता) का उपयोग नहीं हो रहा है तो यह "बेरोजगारी''ही परिभाषित होगी।

भारत में बेरोजगारी उन्मूलन के सन्दर्भ में एक महत्पूर्ण तथ्य यह भी है कि कार्य के बदले अपर्याप्त पारिश्रमिक मिलता है। श्रम सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए लोग कार्य तो करते हैं और सम्भवतः पूरी मेहनत और पूरे समय काम करते हैं, लेकिन उनका उपार्जन इतना कम होता है कि वे गरीबी की रेखा–पार नहीं कर पाते हैं। रोजगार के इसी आयाम को दाण्डेकर ने इंगित करते हुए कहा था कि–"रोजगार के पर्याप्तता की परिभाषा आबादी को निम्न जीवन–स्तर देने की क्षमता से की जानी चाहिए"

हमारी वर्तमान आर्थिक–प्रणाली में बेरोजगारी, मानवीय संसाधनों की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। बेरोगार हाथ आर्थिक क्षति के लक्षण है। देश में बेरोजगारी कोई पृथक आर्थिक आयाम नही है। वह अधूरे विकास और पिछडेपन की आम–समस्या का एक महत्वणर्ण

Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

भाग है। योजना विदों ने इस समस्या की बढ़ती हुई गम्भीरता को भिन्न–भिन्न तरह से बतानें का प्रयास किया है, जैसे–आबादी में तीव्र वृद्धि, रोजगार–परक शैक्षणिक–प्रणाली का अभाव, दोषपूर्ण–नियोजन, अक्षम कार्यान्वयन और शारीरिक श्रम के प्रतिलोगों की उदासीनता तथा कुटीर और ग्राम्य उद्योगों की उपेक्षा इत्यादि। यद्यपि निर्धारित योजना अवधियों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च की जाती है, और प्रत्येक योजना में इस पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन सच यह कि प्रत्येक पाँच–वर्ष में यह समस्या समाप्त होने के बजाय और विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि नियोजित आर्थिक–विकास के पिछले पॉच दशकों में योजना की रणनीति संसाधनों तथा कार्यकारी जनशक्ति का यथोचित उपयोग करने में सफल नहीं रही है। इसके अलावा मूल कारण यह भी है कि विकास की प्रक्रिया में रोजगार सृजन को एक अलग दृष्टिकोण समझा जाता है, और इस तरह रोजगार पैदा करने वाली नीतियों को अलग कर दिया जाता है।

परिणामतः आर्थिक विकास और रोजगार सूजन में कोई समन्वय नहीं हो पाता। इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है कि देश के आर्थिक–विकास और रोजगार नीति के बीच कभीं महत्वपूर्ण सकारात्मक समन्वय रहा ही नहीं। उत्पादकता और रोजगार आर्थिक–विकास की प्रक्रिया के दो पहलू हैं। इसलिए विकास और रोजगार को दो अलग–अलग उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए। व्यापक तौर पर आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि देश में सम्पूर्ण विकास सभी क्षेत्रों में लक्ष्य से नीचे ही रहा है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। हाल के वर्षों में हुए प्रौद्योगिकीय–परिवर्तनों से यद्यपि रोजगार–सृजन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है फिर भी उत्पादन–स्तर में वृद्धि हुई है। विकसित पूँजीवादी देशों की नकल करते हुए भारत जैसे विकासशील देशों ने भी पूँजी आधारित प्रौद्योगिकी का आश्रय लिया है, जिससे रोजगार का इतना सृजन नहीं हो पाया जिससे कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनशक्ति उसमें समाविष्ट हो सके और उन बेरोजगार व्यक्तियों की ओर ध्यान दिया जा सके जो बहुत समय से रोजगार पाने की आशा में हैं। भारत सरकार द्वारा इसके लिए नयी योजनाओं के द्वारा प्रयास भी किये जा रहे है। ''आत्मनिर्भर भारत'', ''ग्राम स्वावलम्बन योजना'', ''राष्ट्रीय कौशल विकास

Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

योजना'', ''लोकल के प्रति वोकल योजना'' एवं प्रत्येक जिला एक उत्पाद जैसे कई योजनाएँ इसी प्रयास का प्रतिफल है।

Airo International Research Journal
ISSN: 2320-3714
July 2020, Volume 22

– : सन्दर्भसंख्या : –

1. मुखर्जी, डी0, "इकोनोमिक प्लानिंग, इम्प्लायमेण्ट जनरेशन एण्ड पावर्टी इराडिकेशन– ",– "खादी ग्रामोद्योग, वाल्यूम 25, नं0 3,
2. मुखोपाध्याय, बी, के0, "अन इम्प्लायमेण्ट इन वेस्ट, मेन स्ट्रीम, वाल्यूम 22, नं0 30, मार्च 24।
3. राजाकृष्णा, "ड्राफ कट फाइव ईयर प्लान 4978–83, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली।
4. भरद्वाज, आर0 सी0, "अन इम्प्लायमेण्ट इन अन्डर डेंवल्ब्ड कन्ट्रीज" एडीटेड बाई वी0 के आर0 वी0 राव, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
5. हजारी, भारत आर0, "द स्ट्रक्चर आफ द इण्डियन इकोनामी", द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।
6. दाण्डेकर, बी0 आर0 एण्ड रथ, एन0, "पावर्टी आफ इण्डिया", इण्डियन स्कूल पोलीटिकल इकोनामी, लोनावाला।
7. सिंगर, एच0 डब्लू0, "अन इसम्प्लायमेण्ट एण्ड द अन इम्प्लायड, पी0 एस0 किंग एण्ड संस लिमिटेड, लन्दन।